

# भागीदारी वकेंद्रीकृत योजना के संदर्भ में ब्लॉक (पंचायत स मर्ति) स्तर पर योजना की समझ

डॉ. पी.आर. शर्मा ,  
(पंचायती राज के **ADVISOR**)

## वकेंद्रीकरण की अवधारणाएं

- ❖ बेहतर आवंटी दक्षता (**allocation Efficiency**) के लिए लोगों के निर्णय - लोग कन सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं (और वोट) करते हैं
- ❖ राजकोषीय तुल्यता (**fiscal equivalency**) का सद्धांत - यदि राजनीतिक क्षेत्रा धकार (jurisdiction) लाभ क्षेत्र के साथ मेल खाता है, तो सीमांत लाभ उत्पादन की सीमांत लागत (सेवा वतरण) के बराबर होता है - सार्वजनिक सेवाओं के इष्टतम प्रावधान में मदद करता है
- ❖ वकेंद्रीकृत प्रमेय (**theorem**) - प्रत्येक सार्वजनिक सेवा न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले क्षेत्रा धकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जो इस तरह के प्रावधान के लाभ और लागत को आंतरिक करेगी
- ❖ सहायता का सद्धांत - कर लगाने, खर्च, नियामक अभ्यास सरकार के निचले स्तर द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए जब तक कि वहां एक ठोस कारण उच्च सरकार को आवंटित करने के लिए हो

# योजना की अवधारणा

- ❖ योजना विकास के एक स्तर से उच्च स्तर पर जाने की एक प्रक्रिया है जैसा कि कुछ मानक ढांचे के अनुसार और स्थानीय संदर्भ में इसे प्राथमिकता देने के लिए तय किया गया है।
- ❖ प्रगति को आंकने के तरीके : (i) वषयगत क्षेत्र जिन पर विकास मापा जाता है, (ii) व भन्न श्रेणियों के लोगों में और (iii) व भन्न क्षेत्रों में
- ❖ सरकार आम तौर पर योजनाओं का निर्माण वषय/ वषयगत क्षेत्र के एक क्षेत्राधिकार तत्व के रूप में जिम्मेदार, जवाबदेह के निर्वाहन के लिये कि अच्छी तरह करते हैं
- ❖ वे उन मामलों पर अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों की स्थिति में सुधार कर सकते हैं, जिनके लिए कोई अन्य सरकार जिम्मेदार है (उदाहरण के लिए, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम ज्यादातर उन वषयों पर हैं जिन पर राज्य जिम्मेदार हैं लेकिन केंद्र सरकार अपने संसाधनों का आवंटन करती है)
- ❖ योजना में विकास के किसी भी वषय (क्या) में सुधार करने के लिए संसाधनों का आवंटन शामिल है (ii) लोगों के कुछ समूह (किसके लिए) के लिए होना चाहिए, (iii) एक क्षेत्राधिकार (कहां) के लिए और कुछ प्रक्रिया (कैसे) का पालन करना पड़ता है - वषय का प्रयोग करके क्या बकसत करना है, किसके लिए, कहां और कैसे।

## वकेंद्रीकृत भागीदारी योजना के लए तर्क

- ❖ योजना वकास के कई आयामों में प्रगति के लए है जो दूसरे शब्दों में लोगों की व भन्न जरूरतों को पूरा करती है
- ❖ इसके अलावा, जरूरतों को टिकाऊ आधार पर पूरा कया जाना है - जिसका अर्थ है वकास की सही प्र क्रया:
- ❖ प्र क्रया जन केंद्रित होनी चाहिए जिसमें लोग वकास का वषय हों न क वकास का उद्देश्य
  - i) इस तरह के वकास को सुगम बनाया जाना चाहिए ना की ऊपर से नियंत्रित कया जाना चाहिए
  - ii) वकास को सशक्त बनाना चाहिए और निर्भरता को कम करना चाहिए
  - iii) इस प्र क्रया को पहले प्रासंगक कारकों, अवसरों और बाधाओं के साथ समस्या को आंतरिक बनाने के साथ शुरू करना चाहिए और इस बात पर काम करना चाहिए क लोगों/सरकार के स्तर पर कया कया जाना संभव है और फर लोगों/सरकार के पास जो कुछ नहीं है उसके लए समर्थन की तलाश है ।
  - iv) इस तरह का समर्थन - फंड, प्रौद्योगिकी, कौशल, क्षमता आदि है।

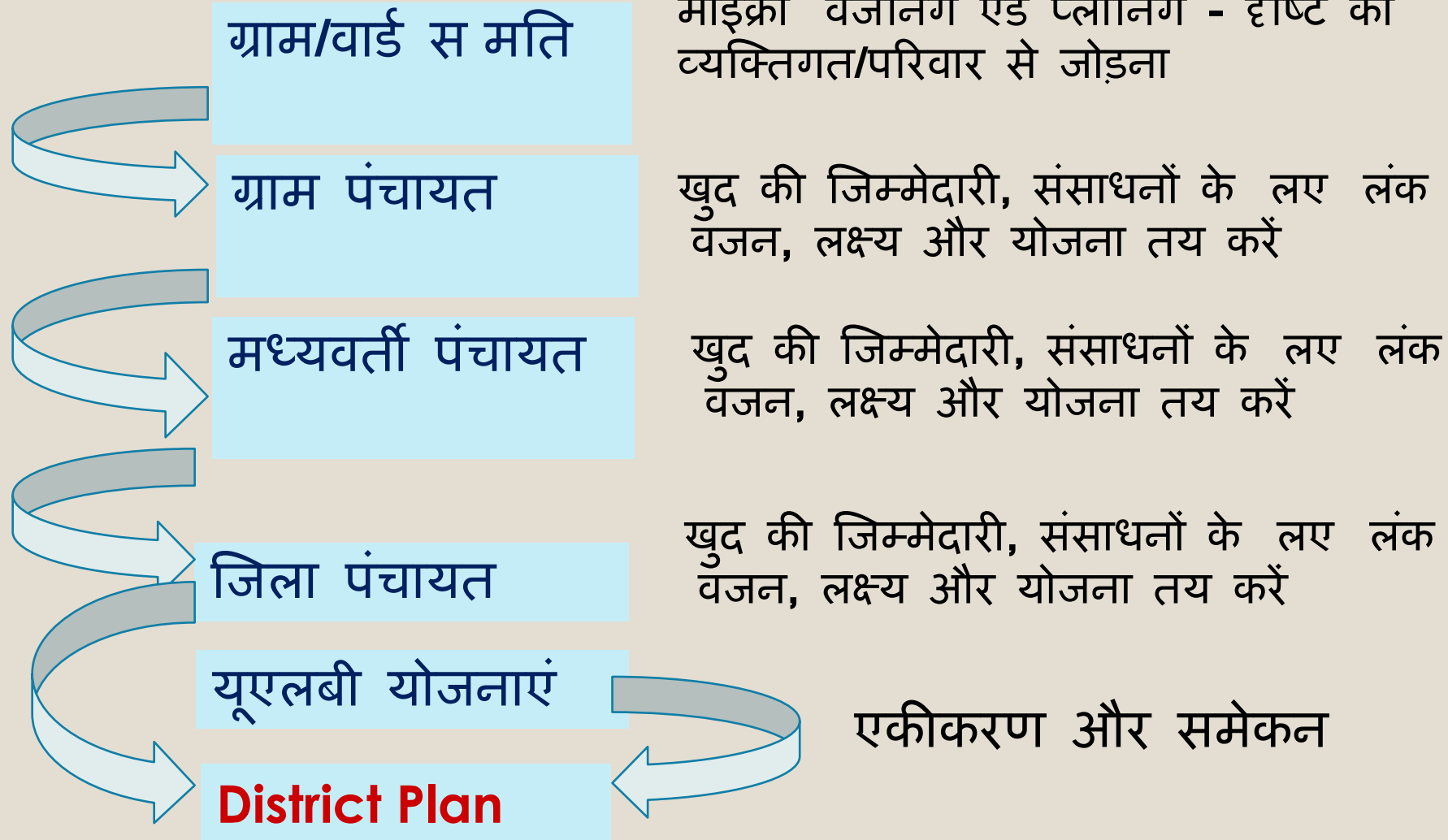
## वकेंद्रीकृत भागीदारी योजना के लए तर्क

- ❖ योजना सरकार के पास उपलब्ध फंड के साथ कसी भी क्षेत्र में शुरू नहीं कया जा सकता
- ❖ इस लए, लोगों की समस्या/आवश्यकताओं को प्रारंभक गति व ध के रूप में आंका जाना चाहिए- उनकी समस्याओं का समाधान लोगों द्वारा (नो/लो कॉस्ट गति व धयां), (ii) जीपी, (iii) पीएस, (iv) जेडपी या (v) उच्च स्तरीय सरकार द्वारा कया जा सकता है ।
- ❖ लोगों की आवश्यकता का आकलन करने के लए लोगों की भागीदारी, जिसे लोग वकेंद्रीकृत स्तर पर बाधाओं को कम कर सकते हैं और उनकी पहचान कर सकते हैं, यह प्रदान कर सकते हैं क लोगों की अपनी पहलों सहित सरकार का कौन सा स्तर कसी भी इलाके के सामने आने वाली समस्या का समाधान कर सकता है
- ❖ उस मामले में लोग योजना के मा लक बन जाते हैं न क लाभार्थी
- ❖ लोगों को मैक्रो-इश्यू (एसडीजी) के बारे में जानकारी नहीं है या मुद्दों की कल्पना /मात्र नहीं कर सकते जैसे जलवायु परिवर्तन, आपदाएं आदि जिसके लए उच्च स्तर से इनपुट की आवश्यकता होती है ।
- ❖ योजना नीचे (grassroot) से शुरू करने के लए है, ऊपर (top level) के अच्छी सु वधा के साथ

## योजना का एकीकरण और समन्वय

- ❖ जीपीडीपी उन मुद्दों के समाधान के लिए तैयार और कार्यान्वित किया जाता है जो स्थानीय हैं और व भन्न सेवाओं को वतरित करने के लिए जीपी की जिम्मेदारी रखते हैं
- ❖ पहचानी गई कई समस्याओं का जीपी स्तर पर समाधान नहीं किया जा सकता क्यों क- (i) हस्तक्षेपों की बाह्यता, (ii) अपर्याप्त संसाधनों या (iii) जीपी की क्षमता से अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता ।
- ❖ उन कार्य को पीएस पर भेजा जाना है ता क व्यवहार्यता जांच की जा सके क उनके स्तर पर क्या ध्यान रखा जा सकता है
- ❖ पीएस को जीपीएस द्वारा उन्हें संदर्भित (i) समस्याओं के आधार पर योजना बनानी होती है (पीआरए टूल/सर्वेक्षण का उपयोग करके एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर, (ii) अपने सदस्यों द्वारा पहचानी गई समस्याएं, (iii) माध्यमिक आंकड़ों का विश्लेषण, यदि संभव हो तो जीपी स्तर तक वच्छेदन के साथ,
- ❖ इसी प्रकार, जिन समस्याओं का समाधान पीएस स्तर पर नहीं किया जा सकता है, उन्हें जेडपी के पास भेजा जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो जेडपी के माध्यम से राज्य स्तर पर भेजा जाना चाहिए ।
- ❖ जो कहा गया है वह आसान है, जो व भन्न स्तरों और व भन्न वभागों में उचित समन्वय की आवश्यकता है ।

# व भन्न स्तरों की योजनाओं के एकीकरण की चुनौती



## मध्यवर्ती पंचायतों द्वारा योजना का महत्व

- ❖ योजना बनाने के लिए कानूनी जनादेश - संवधान के तहत प्रदान किए गए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए
- ❖ सभी लाइन विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति: मध्यवर्ती पंचायत (आईपी या पीएस) ब्लॉक के साथ सहसंबद्ध होने के नाते, इसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति है
- ❖ उच्च क्षमता जीपीडीपी की गुणवत्ता में सुधार और प्रासंगिक लाइन विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ❖ माध्यमिक डेटा की उपलब्धता विश्लेषण करना आसान बनाता है और विभिन्न संवधानों के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार और सेवा क्षेत्रों के बीच बेमेल की समस्या आम तौर पर नहीं होती है - इस लिए जीपीएस को योजना बनाने के लिए ब्लॉक/जीपी स्तर के आंकड़ों के साथ संवेदनशील किया जा सकता है
- ❖ जीपीएस के कामकाज का अवलोकन करने के लिए जनादेश - पीएस जीपीएस द्वारा योजना का अवलोकन करने और उच्च स्तर तक बड़े मुद्दों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर पर खड़ा है



## मध्यवर्ती पंचायतों द्वारा योजना में बाधाएं

- ❖ राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी के साथ-साथ पीएसडीपी के लिए फ्रेमवर्क / गाइडलाइंस की कमी
- ❖ पीएस/ ब्लॉक की क्षमता पछले कुछ वर्षों में घट गई है और कई वभागों का मानना है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए - नियंत्रण के बिना समन्वय कैसे सुनिश्चित किया जाए?
- ❖ कमजोर/कोई स्थायी समितियां नहीं- संबंधित लाइन वभागों के अधिकारियों की भागीदारी के साथ निर्दिष्ट वर्षों से निपटने के लिए-संस्थागत तंत्र की कमी
- ❖ योजना प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित तकनीकी मानव शक्ति की कमी
- ❖ पीएसएस के अपने स्रोत राजस्व के साथ-साथ योजना के लिए हकदार निधि की कमी

## पीएस की अन्य बाधाएं

- ❖ पीएस पर शक्तियों/ जिम्मेदारियों का थोड़ा औपचारिक हस्तांतरण
- ❖ ब्लॉक अधिकारियों को आम तौर पर पीएस के अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए तैनात किया जाता है - इसके मुख्य संस्थागत कामकाज का ख्याल रखने के लिए पीएस को परेशानी होती है
- ❖ पीएस के सदस्य वषयगत वषयों पर उन्मुख नहीं होते हैं जो लाइन वभागों के अधिकारियों द्वारा प्रशासित होते हैं - इस लिए समन्वय मुश्किल हो जाता है
- ❖ दिशा-निर्देशों की कमी/उचित मान सकता कैसे लाइन वभागों की सेवाओं का उपयोग पीएस द्वारा किया जा सकता है, भले ही वे पीएस द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित न हों
- ❖ स्पष्ट डिलवरेबल्स के साथ साक्ष्य के आधार पर वस्तुनिष्ठता के साथ योजना बनाने के लिए डेटा का विश्लेषण करने के लिए डेटा/क्षमता की कमी

## पीएस स्तर पर साक्ष्य आधारित योजना

- ❖ पीएस को विकास के व भन्न वर्षों पर ब्लॉक वार स्थिति संकलित करने और जीपीडीपी के लिए प्राथमिक डेटा कैप्चर करने के लिए जीपीएस का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ पीएस को ब्लॉक डेटाबेस बनाने में मदद करने की क्षमता की आवश्यकता है
- ❖ राज्य को डेटाबेस के विकास में सहायता करने और डेटा संग्रह और प्रबंधन (डीआईएसई/एचएमआईएस/आईसीडीएस एमआईएस आदि) का ढांचा उपलब्ध कराने की जरूरत है।
- ❖ स्थानिक योजना की कल्पना करने और अभिसरण में मदद करने के लिए जीपीएस दिखा पीएस के स्थानिक नक्शे
- ❖ डेटा का विश्लेषण करने और एसडीजी संकेतकों पर स्थिति दिखाने वाली विकास स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर) को संकलित करने के लिए पीएस की निर्माण क्षमता- जो प्रगति की योजना और मापने के लिए परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है
- ❖ जीपीएस में प्रगति का यथासंभव विश्लेषण करें, विकास के प्रत्येक मद के लिए जीपीएस रैंक करें और अधिक इक्विटी लाने और कुछ जीपीएस में बड़े अंतराल को पाटने के लिए निवेश करें - इस तरह के विश्लेषण से जीपीडीपी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा
- ❖ निर्माण क्षमता एक बड़ी चुनौती है

## PSDP के लिए Way Forward

- ❖ राज्य सरकार को व शष्ट अ धदेश देने के लिए एनआईआरडीपीआर/एमओपीआर द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के आधार पर एक आदेश जारी करना होगा।
- ❖ मानव विकास और आजीविका के व भन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के आंकड़ों के वश्लेषण और व्याख्या/एमएंडई/इंजीनियरिंग/आईटी/ व भन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए क्षमता के साथ एक सम र्पत टीम की आवश्यकता
- ❖ सभी लाइन वभाग प्रत्येक ब्लॉक के लिए अपनी जिम्मेदारियों के संबंध में प्रगति की स्थिति संक लत करने और स्थिति और उनकी प्राथ मकताओं को समझाने के लिए जिला स्तर पर प्र शक्षण का आयोजन
- ❖ एक ल खत दस्तावेज के रूप में प्रत्येक पीएस के लिए डीएसआर की तैयारी, जिसे सभी हितधारकों को साझा करने की आवश्यकता है
- ❖ मुद्दों को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए वभागीय अ धकारियों/ वशेषज्ञों/निर्वा चत पदा धकारियों की भागीदारी से प्रत्येक वषय पर विकास संगोष्ठी
- ❖ विकास की क मयों, प्राथ मकताओं की पहचान करें और संसाधन को भी बाहर निकालने का करें। ब्लॉक स्तर पर संस्थागत वत्त, कौशल विकास, आईईसी/एसबीसीसी की आवश्यकता की पहचान और हस्तक्षेप योजनाओं के साथ-साथ निगरानी का काम करना भी सार्थक होगा।

धन्यवाद